माध्यमिक शिक्षा बोर्ड असम

बनाम

एम. डी. सरिफुज़ ज़मान और अन्य

19 दिसंबर, 2003

[न्यायाधिपति आर. सी. लाहोटी और न्यायाधिपति अशोक भान]

असम माध्यमिक परीक्षा बोर्ड द्वारा परीक्षा आयोजित करने के लिए विनियमः विनियमन 8- जन्म तिथि में सुधार- सुधार के लिए आवेदन दायर करने के लिए तीन साल की अवधि प्रदान करने वाला विनियमन- बोर्ड ने आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि यह सीमा की अवधि से परे दायर किया गया था- उच्च न्यायालय ने राहत की अनुमति दी- आयोजित, तीन साल की अवधि विनियमन द्वारा प्रदत्त एक बहुत ही उचित अवधि है- प्रावधान न तो अवैध है और न ही अधिनियम की धारा 24 के दायरे से बाहर है। और इसे मनमाना या अनुचित भी नहीं कहा जा सकता है- तीन साल की अवधि के भीतर सुधार की मांग करने वाले आवेदक स्वयं एक वर्ग बनाते हैं और इस तरह के पर्चे का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध है जिसे प्राप्त करने की मांग की गई है-संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान पर कोई दोष नहीं पाया जा सकता है-उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार कर दिया गया है-हालांकि, बोर्ड की ओर से दी गई रियायत को देखते हुए, इस निर्णय का दो उत्तरदाताओं को दी गई राहत पर कोई असर नहीं होगा-भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 14- असम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1961-धारा 24।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील संख्या 10250/2003

(गुवाहाटी उच्च न्यायालय के 2000 के डब्ल्यू. ए. संख्या 343 में दिनांक 30.8.2000 के निर्णय और आदेश से।)

के साथ

सी. ए संख्या 10251/2003

अपीलार्थियों की ओर से पी. के. गोस्वामी, राजीव मेहता और बी. अग्रवाल। उत्तरदाताओं के लिए सुश्री के. शारदा देवी।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया थाः

दोनों एसएलपी में अनुमति दी जाती है।

समान तथ्यों की पृष्ठभूमि में इन दोनों अपीलों में निर्णय के लिए कानून के सामान्य प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यह हमारे उद्देश्य को एक मामले के तथ्य ध्यान में रखने के लिए पर्याप्त होगा।

उत्तरदाताओं में से एक छात्र ने सरकारी बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल में अपनी शिक्षा प्राप्त की थी और वर्ष 1991 में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, असम द्वारा आयोजित मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इसके बाद, उसने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण की और फिर बी.एससी. वर्ष 1998 में परीक्षा उत्तीर्ण की। जब उन्होंने रिट याचिका दायर की, तो वे कंप्यूटर में अध्ययन कर रहे थे। उस समय, 12 अक्टूबर, 1999 को, उन्होंने बोर्ड को एक आवेदन दिया जिसमें शिकायत की गई थी कि उनकी जन्म तिथि गलत तरीके से स्कूल के रिकॉर्ड में 30 मई, 1974 के रूप में उल्लिखित की गई थी, जबकि उनकी वास्तविक जन्म तिथि 16 अगस्त, 1975 थी। बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रवेश पत्र में गलत जन्म तिथि, जैसा कि स्कूल द्वारा अग्रेषित की गई थी, सामने आ गई थी।

रिट-याचिकाकर्ता छात्र ने दलील दी कि उसे स्कूल के रिकॉर्ड में दर्ज की जाने वाली सही जन्म तिथि के महत्व का एहसास नहीं था, और इसलिए, उसे तब तक इसके निहितार्थ का भी एहसास नहीं था जब तक कि उसे आवेदन दायर करने में

पदोन्नत नहीं किया गया था। प्रत्यर्थी द्वारा स्कूल के प्राचार्य को दिया गया आवेदन, बाद में बोर्ड को भेज दिया गया था। प्रधानाचार्य ने संकेत दिया कि प्रत्यर्थी की आयु प्रवेश रजिस्टर में 16.8.1975 के रूप में दर्ज की गई थी लेकिन गलती से बोर्ड परीक्षा का फॉर्म भरते समय जन्मतिथि 30.5.1974 दर्ज हो गई थी। प्रिंसिपल ने गलती को 'अपमानजनक' बताया और इसमें सुधार की सिफारिश की. चूंकि बोर्ड ने कोई निर्णय नहीं लिया आवेदन पर, प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की। बोर्ड ने बोर्ड द्वारा परीक्षाओं के संचालन के लिए विनियमों के विनियमन पर भरोसा किया, (इसके बाद संक्षेप में 'विनियम'), के अभ्यास में तैयार किया गया। असम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 (इसके बाद 'अधिनियम', संक्षेप में) की धारा 24 द्वारा प्रदत्त शक्तियां और प्रस्तुत किया गया कि बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख से तीन साल से अधिक समय के लिए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिका को उच्च न्यायालय का समर्थन मिला जिसके परिणामस्वरूप रिट याचिका खारिज कर दी गई। प्रतिवादी द्वारा एक रिट अपील को प्राथमिकता दी गई थी। प्रभाग पीठ ने अपील को स्वीकार कर लिया है, विद्वान एकल बोर्ड के फैसले को रद्द कर दिया है।और प्रतिवादी द्वारा रिट जारी करके मांगी गई राहत की अनुमति दी है।

बोर्ड के परमादेश से व्यथित महसूस करते हुए, बोर्ड ने विशेष अनुमति द्वारा ये अपीलें की हैं।प्रारंभ में, अपीलकर्ता-बोर्ड के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि बोर्ड को यहां दो उत्तरदाताओं को दी गई राहत को रद्द करने में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह कानूनी स्थिति को तय करने में रुचि रखता था, जहां तक कि कानून के दृष्टिकोण को ध्यान में रखा गया था। डिवीजन बेंच के परिणामस्वरूप बोर्ड में आवेदकों की दर्ज की गई जन्म तिथियों में सुधार की मांग करने वाले आवेदनों की बाढ़ आ गई है।

बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने के परिणामस्वरूप उन्हें प्रमाण पत्र जारी किए जाते है। उच्च न्यायालय द्वारा अपनाए गए उदार दृष्टिकोण का अनुचित लाभ उठाने वाले बेईमान आवेदकों की संभावना के परिणामस्वरूप गैर-वास्तविक मामलों का भी निपटारा किया जा सकता है, जिन पर वहां नियंत्रण रखना मुश्किल होगा। इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों के मद्देनजर, हम विनियमन 8 के संदर्भ में जन्म तिथि में सुधार की मांग करने के लिए बाहरी सीमा के रूप में निर्धारित 3 साल की अवधि की वैधता के बारे में कानून की जांच, निपटान और समझौता करने का प्रस्ताव करते हैं।

उच्च न्यायालय के फैसले के अवलोकन से पता चलता है कि बोर्ड के खिलाफ राय बनाने और रिट-याचिकाकर्ताओं को राहत देने में उच्च न्यायालय के साथ मुख्य रूप से दो कारण प्रबल हैं। उच्च न्यायालय ने सबसे पहले यह अभिनिर्धारित किया है कि अधिनियम की धारा 24 में विनियमों पर विचार किया गया है केवल अधिनियम के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड के कामकाज और कार्यप्रणाली को सुविधाजनक बनाने के लिए बनाया गया है; विनियम इस तरह से नहीं बनाए जा सकते हैं कि किसी भी आवेदक को आवेदन करने के लिए सीमा की अवधि साबित करके जन्म तिथि में सुधार करने के अधिकार से वंचित किया जाए; और दूसरा, क़ानून के प्रावधानों को पूरा करने के उद्देश्य से बनाए गए विनियमों में किया गया कोई भी प्रावधान गलती सुधारने के लिए किसी व्यक्ति के लिए आम तौर पर उपलब्ध किसी भी अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता है।कोई भी नियामक उपाय किसी भी मामले में पूर्ण प्रकृति का नहीं हो सकता है। अपीलार्थी के विद्वान वकील ने उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रस्ताव की शुद्धता पर विवाद किया है। आइए हम जांच करने के लिए आगे बढ़ें

बोर्ड का गठन असम माध्यमिक शिक्षा अधिनियम, 1961 के तहत किया गया है और इसके तहत इसका अधिकार प्राप्त होता है। धारा 24 की उपधारा (I) बोर्ड को यह अधिकार देती है।

अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से आम तौर पर विनियम बनाना। धारा 24 की उप-धारा (2) खंड (ए) से (एम) द्वारा विशेष रूप से उन विषयों को निर्धारित करती है जिन पर बोर्ड शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना विनियम बना सकता है। उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त।

विनियमन 8 निम्नानुसार प्रदान करता है -

"8. जन्मतिथि, नाम, पदवी आदि में सुधार।

(ए) जन्म तिथि: एक बार जब जन्म तिथि निर्धारित राज्य में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल / मदरसा / हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रमुखों द्वारा बोर्ड को सूचित कर दी जाती है, तो परीक्षा के लिए आवेदन के साथ उम्मीदवारों को सौंप दिया जाता है और रिकॉर्ड में दर्ज कर दिया जाता है। बोर्ड की ओर से, इसमें गलत गणना या लिपिकीय त्रुटि के अलावा कोई बदलाव नहीं किया जाएगा, जिसके लिए संस्थान के प्रमुख की सिफारिश के साथ संबंधित स्कूलों के निरीक्षक के माध्यम से बोर्ड को आवेदन करना होगा जो स्कूल के रिकॉर्ड को सत्यापित करेगा और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करें. यदि बोर्ड का सचिव इस बात से संतुष्ट है कि गलत गणना या लिपिकीय त्रुटि के कारण जन्मतिथि की गलत रिपोर्ट दी गई है तो वह सुधार के लिए आदेश पारित कर सकता है। :

बशर्ते कि जन्म तिथि 30 फरवरी, 31 अप्रैल, 31 जून, 31 सितंबर, 31 नवंबर और 29 फरवरी को भी लीप वर्ष को छोड़कर महीने की अंतिम तिथि के रूप में समान रूप से सुधार किया जाना चाहिए, स्कूल के किसी भी संदर्भ के बिना ।

यदि प्रमाणपत्र लिखने के चरण में ही कोई अशुद्धि रह जाती है, तो अन्य सभी पूर्व दस्तावेज़ सभी प्रकार से सही होने पर, आवेदन प्राप्त होने पर प्रमाणपत्र में सुधार स्वीकार्य होगा। आवश्यक शुल्क के साथ बोर्ड द्वारा प्रमाण पत्र जारी होने की तारीख से 3 वर्ष के भीतर।

XXX XXX XXX XXX

निस्संदेह, अधिनियम की धारा 24(1) द्वारा बोर्ड को प्रदत्त सामान्य शक्ति अधिनियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने के उद्देश्य से है; धारा 24(2) के तहत, खंड (डी) विषय प्रदान करता है, जिस पर परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्रकाशित करने जैसे विनियम बनाए जा सकते हैं। खंड (जी) विषय को उन शर्तों के रूप में प्रदान करता है जिनके तहत उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। यह विवादित नहीं है, और न ही हो सकता है कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार का आवेदन पत्र उस शैक्षणिक संस्थान द्वारा अग्रेषित किया जाना चाहिए जहां वह पढ़ रहा है। आवेदन विधिवत, वास्तविक और पूर्ण रूप से भरा जाना चाहिए। दी जाने वाली आवश्यक सूचनाओं में से एक है छात्रों की आयु और जन्म तिथि। यह सामान्य ज्ञान है कि बोर्ड द्वारा मैट्रिक परीक्षा या उच्चतर माध्यमिक स्तर की परीक्षा में जारी प्रमाण पत्र में छात्र की जन्म तिथि का उल्लेख होता है। इस तरह के प्रमाणपत्र को आवेदक के आगे के करियर के दौरान उसकी जन्मतिथि और उम्र के प्रमाण में एक मूल्यवान साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।"

परिणामतः खंड (छ) विषय को ऐसी शर्तों के रूप में प्रदान करता है जिनके तहत उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा। यह विवादित नहीं है,

और यह नहीं हो सकता है कि बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में भाग लेने के इच्छुक उम्मीदवार का आवेदन पत्र होना चाहिए।

कानून की अदालतें प्रमाण पत्र के लिए उच्च स्तर का संभावित मूल्य जोड़ती हैं और इसके विपरीत कुछ भी नहीं होने पर, प्रमाण पत्र में दर्ज जन्म तिथि को लगभग बाध्यकारी के रूप में स्वीकार किया जाता है। बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के परिणाम प्रकाशित होने पर सफल उम्मीदवारों को पुरस्कृत किया जाता है। प्रमाण पत्र, नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, जिस संस्थान में छात्र ने अध्ययन किया है और ऐसे अन्य विवरण जो प्रमाण पत्र में शामिल हैं, आवेदन पत्र की सामग्री द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी पर आधारित हैं, जिसकी जांच, सत्यापन और उस संस्थान द्वारा अग्रेषित किया जाता है, जिसमें छात्र ने अध्ययन किया है। इन सभी विवरणों में उनके साथ शुद्धता की प्रथम दृष्टया गारंटी होती है क्योंकि संस्थान के रिकॉर्ड में ऐसे विवरण स्वयं आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और आवेदक स्वयं बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन भरता है और सदस्यता लेता है।

जहां तक आवेदक का सवाल है, यह मानना मुश्किल है कि ऐसे विवरण गलत या गलत होंगे। साथ ही, यह प्रक्रिया 'परीक्षा आयोजित करने और परिणाम प्रकाशित करने' की प्रक्रिया का एक हिस्सा बन जाती है और साथ ही उन शर्तों का भी हिस्सा बन जाती है जिनके तहत उम्मीदवारों को बोर्ड की परीक्षाओं में प्रवेश दिया जाएगा' खंड (डी) और में शामिल दो विषय (जी) अधिनियम की धारा 24 की उप-धारा (2), धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति की व्यापकता के अलावा। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता है कि प्रमाण पत्र और इसमें की गई किसी भी प्रविष्टि का सुधार बोर्ड को प्रदत्त विनियम बनाने की शक्ति के दायरे में नहीं आता है।

कोई भी किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र में प्रविष्टि को सही करने के अधिकार का दावा नहीं कर सकता है, वह भी उस संस्थान द्वारा जिसे अधिनियम के तहत वैधानिक बोर्ड का दर्जा प्राप्त है। त्रुटि होने पर आवेदक का अधिकार या गलती को सुधारना बोर्ड की ओर से अपने रिकॉर्ड और उसके द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र को सही करने के कर्तव्य या दायित्व के साथ जुड़ा हुआ है। न केवल यह एक संबंधित कर्तव्य या दायित्व है, बल्कि इसे बोर्ड द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्ति के रूप में भी माना जाना चाहिए। इसके द्वारा जारी प्रमाण पत्र में दिखाई देने वाली प्रविष्टि को सही करने के लिए।

लोग, संस्थाएं और सरकारी विभाग आदि - बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों में की गई प्रविष्टियों के लिए सभी बहुत उच्च स्तर की विश्वसनीयता जोड़ते हैं, जो अंतिम होने के करीब है। प्रमाणपत्रों में प्रविष्टियों को सही करने के लिए शक्ति का बार-बार प्रयोग और वह भी इस तरह की शक्ति के प्रयोग पर किसी भी सीमा के बिना शक्ति को मनमाना बना देगा और इसके परिणामस्वरूप बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्रों की विश्वसनीयता कम हो जाती है। इसलिए, हमें इस तर्क को बनाए रखना मुश्किल लगता है कि ऐसे प्रमाणपत्रों में प्रविष्टियों में सुधार की मांग करने वाले आवेदकों को ऐसा कोई अधिकार या निहित अधिकार है।

अंत में, प्रस्तुतिकरण को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है कि विनियामक उपाय 'के सुधार के विषय पर विनियमों में शामिल किया गया है प्रमाणपत्रों में त्रुटियाँ 'निरपेक्ष' प्रकृति की होती हैं। विनियमन सुधार की अनुमति देता है लेकिन केवल उचित प्रतिबंधों के अधीन है।

विलंब विवेक को पराजित करती है और सीमा का नुकसान उपचार को ही नष्ट कर देता है। विलंब की राशि के परिणामस्वरूप समता के सिद्धांतों पर विवेकाधीन

शक्ति से वंचित होने का लाभ मिलता है। उपचार से वंचित होने के परिणामस्वरूप सीमा का नुकसान, सार्वजनिक नीति और उपयोगिता पर आधारित एक सिद्धांत है, न कि केवल समानता पर। समय की एक सीमा होनी चाहिए जिसके द्वारा मानविय मामले हल हो जाते हैं और अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। विनियम 8 आवेदक को गलत गणना या लिपिकीय त्रुटि के आधार पर जन्म तिथि में सुधार करने के लिए बोर्ड को दायित्व के साथ अधिकार और शक्ति प्रदान करता है। स्कूलों के निरीक्षक के माध्यम से आवेदन को संसाधित करने के लिए एक उचित प्रक्रिया निर्धारित की गई है जो स्कूल के रिकॉर्ड को सत्यापित करेंगे और बोर्ड को रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे ताकि उन दावों के अलावा अन्य दावों को विचार से बाहर रखा जा सके विनियमन 8 के ढांचे के भीतर अनुमेय। सुधार के लिए आदेश पारित करने की शक्ति बोर्ड के सचिव जैसे उच्च पदाधिकारी के पास निहित है।केवल प्रमाणपत्र लिखने के चरण में ही अशुद्धि आ जाती है, जबकि अन्य सभी पूर्व दस्तावेज़ सभी प्रकार से सही होते हैं, ऐसा हो सकता है। जारी होने की तारीख से तीन साल की अवधि के भीतर सही किया गया प्रमाणपत्र का. विनियम द्वारा प्रदान की गई तीन वर्ष की अवधि एक बहुत ही उचित अवधि है। प्रमाणपत्र जारी करने की तारीख पर ही संबंधित छात्र को प्रमाणपत्र में की गई प्रविष्टियों के बारे में सूचित कर दिया जाता है।

हर किसी को उनकी उम्र और जन्म तिथि याद रहती है। छात्र को एहसास होगा कि नहीं उस समय जब प्रमाण पत्र में दर्ज की गई जन्म तिथि सही नहीं है, यदि ऐसा प्रमाण पत्र उसके हाथों में रखे जाने के बाद होता है। प्रमाणपत्र के आधार पर आवेदक किसी शैक्षणिक संस्थान में कहीं और प्रवेश लेगा। या एक नौकरी या कैरियर की तलाश कर सकता है जहाँ उसे अपनी उम्र और जन्म तिथि का उल्लेख करना होगा। भले ही वह प्रमाण पत्र जारी करने की तारीख पर त्रुटि को नोटिस करने में विफल रहे, उन्हें इसके तुरंत बाद पता चल जाएगा। इस प्रकार, विनियमन 3 द्वारा निर्धारित तीन साल

की अवधि काफी उचित है। यह मुकदमा दायर करने के लिए सीमा की अवधि निर्धारित करने जैसा कुछ नहीं है। तीन साल का प्रावधान एक विभाजन जुर्माना निर्धारित करता है जिसके पहले सुधार करने के लिए बोर्ड की शक्ति का उपयोग किया जाना चाहिए और जिसके बाद इसे लागू नहीं किया जा सकता है। विलंबित आवेदन, यदि प्राप्त करने की अनुमति दी जाती है, तो एक पेंडोरा बॉक्स खुल सकता है। अभिलेख उपलब्ध नहीं हो सकते हैं और हो सकता है कि साक्ष्य खो गए हों। ऐसे साक्ष्य-यहां तक कि सुविधाजनक साक्ष्य भी अस्तित्व में लाए जा सकते हैं जो जांच की अवहेलना कर सकते हैं। तीन साल के बार का निर्धारण ऐसी सभी स्थितियों का ध्यान रखता है। यह प्रावधान न तो अवैध है और न ही अधिनियम की धारा 24 के दायरे से बाहर है और न ही मनमाना या अनुचित हो सकता है। तीन साल की अवधि के भीतर सुधार की मांग करने वाले आवेदक स्वयं एक वर्ग बनाते हैं और इस तरह के निर्धारण का उस उद्देश्य के साथ एक उचित संबंध होता है जिसे प्राप्त किया जाना चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 14 में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

पूर्वगामी कारणों से, अपीलों की अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय की खंड पीठ के निर्णय को खारिज कर दिया गया है। लेकिन पहले की तरह विद्वान वकील द्वारा दी गई बहुत ही उचित रियायत को ध्यान में रखते हुए अपीलार्थी बोर्ड के लिए, यह निर्देश दिया जाता है कि इस निर्णय का कोई प्रभाव नहीं होगा या दोनों उत्तरदाताओं को इसमें दी गई राहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उनके संबंधित प्रमाणपत्रों में की गई जन्म तिथि के रूप में प्रविष्टियों को सही करना। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं।

आर. पी.

अपीलों की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता निशा पालीवाल द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।